



## लॉटरी पर कर अधरिपण: सर्वोच्च न्यायालय

### प्रलिमिंस के लयि:

ऑनलाइन गेमगि, जुआ, कर्नाटक पुलसि (संशोधन) अधनियिम, 2021, 'गेम ऑफ स्कलि', 'गेम ऑफ चांस', लॉटरी, सट्टेबाज़ी।

### मेन्स के लयि:

नरिणय और मामले, ऑनलाइन गेमगि और इसके प्रभाव, जुआ, सट्टेबाज़ी एवं लॉटरी से संबंघति कानून।

## चर्चा में क्यौं?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कएक राज्य वधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आयोजति लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है।

- इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलसि (संशोधन) अधनियिम, 2021 के प्रमुख हसिसों को खारजि करते हुए एक नरिणय दयि था, जसिमें ऑनलाइन जुआ और कौशल-आधारति गेमगि (गेम ऑफ स्कलि) प्लेटफॉर्म पर प्रतबिंध लगा दयि गया था।
- वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना क लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी 'वसतु एवं सेवा कर' (GST) अधनियिम, 2017 के तहत कर योग्य है।

## इस नरिणय की पृष्ठभूमि:

- यह फैसला कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा अपने संबंघति उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर दयि गया है, जसिमें केरल एवं कर्नाटक में नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सक्किमि, मणपिर राज्यों द्वारा आयोजति और प्रचारति लॉटरी पर कर लगाने हेतु उनकी वधायिकाओं ने अधनियिमति कानूनों को रद्द कर दयि था।
- उच्च न्यायालयों ने दोनों राज्यों द्वारा बनाए गए कर कानूनों को अमान्य और असंवैधानकि पाया था और यहाँ तक क केरल एवं कर्नाटक को लॉटरी से कर के रूप में एकत्र कयि गए धन को उत्तर-पूर्वी राज्यों को वापस करने का नरिदेश दयि था।

## सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- न्यायालय ने पाया क 'लॉटरी' एक 'जुआ गतविधि' है।
  - 'सट्टेबाज़ी और जुआ' संवधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का वषिय है।
  - ऐसे में राज्य सरकार को उन सभी गतविधियों पर कर अधरिपति करने की शक्तिप्राप्त है, जो लॉटरी सहति 'सट्टेबाज़ी और जुआ' की प्रकृति की हैं।
  - सट्टेबाज़ी और जुआ एक प्रकार की व्यापक श्रेणी है जसिमें घुड़दौड़, वहीलगि व अन्य स्थानीय सट्टेबाज़ी एवं जुआ से संबंघति गतविधियाँ शामिल हैं।
- अदालत ने कहा क चूँक इस बात पर कोई वविद नहीं है क लॉटरी भारत सरकार या राज्य सरकार या राज्य द्वारा अधिकृत है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कसि एजेंसी या संस्था या कसि नजि अभकिर्त्ता द्वारा संचालति व आयोजति 'सट्टा और जुआ' है तथा राज्य वधियानसभाओं के पास राज्य सूची की प्रवषिटि 62 के तहत लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है।
  - उक्त प्रवषिटि के तहत करधान में सट्टेबाज़ी और जुआ जैसी गतविधियों को शामिल कयि जाता है जसिमें लॉटरी भी शामिल है, भले ही इनका संचालन कसि भी संस्था द्वारा कयि जाता हो।

## लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी से संबंघति केंद्रीय कानून:

- लॉटरी (वनियिमन) अधनियिम, 1998:
  - इस अधनियिम के तहत भारत में लॉटरी को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा कयि जाना

चाहयि और लॉटरी के डरों का स्थान भी उस राज्य वशिष में ही होना चाहयि ।

- **भारतीय दंड संहति, 1860:**
  - यद कोई सार्वजनकि स्थान पर अश्लील कार्य करता है या कसिी भी सार्वजनकि स्थान या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत गाता है या बोलता है तो संहति में इससे संबंधति दंड का प्रावधान है ।
  - यद सिट्टेबाज़ी और जुए की गतविधियों के वजिज़ापन के लयि कोई अश्लील सामग्री का उपयोग करता है तो आईपीसी के प्रावधान लागू हो सकते हैं ।
- **वदिशी मुद्रा परबंधन अधनियिम, 1999:**
  - इस अधनियिम के तहत लॉटरी, रेसगि/राइडगि से अरजति आय के प्रेषण को प्रतबंधति कयिा जाता है ।
- **सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021:**
  - इन नयिमों के तहत कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता या कोई भी सर्च इंजन ऐसी कसिी भी सामग्री को उपलब्ध नहीं कराएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुए (Gambling) का समर्थन करती हो ।
- **आयकर अधनियिम, 1961:**
  - भारत में वर्तमान कराधान नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के जुआ उद्योग को शामिल करती है । इस प्रकार कहा जा सकता है कसिी भी प्रकार से वनियिमति एवं वैध जुआ भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP)** द्वारा समर्थति है ।

## वगित वर्षों के प्रश्न

भारतीय संसद को राष्ट्रीय हति में राज्य सूची के कसिी वषिय या वस्तु पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, उस प्रस्ताव को नमिनलखिति में से कसिके द्वारा पारति कयिा जाता है? (2016)

- (a) लोकसभा की कुल सदस्यता के साधारण बहुमत द्वारा
- (b) लोकसभा की कुल सदस्यता के कम-से-कम दो-तहिाई बहुमत द्वारा
- (c) राज्यसभा की कुल सदस्यता के साधारण बहुमत द्वारा
- (d) राज्यसभा के उपस्थति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तहिाई बहुमत द्वारा

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-on-taxing-lotteries>